ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बनाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र :** अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत के हित

प्रसंग

- विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निधि का प्रबंध करने के लिए विश्व के सबसे अमीर व लोकतांत्रिक देशों के संगठन जी-7 ने संयुक्त पहल के रूप में आधिकारिक रूप से ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट (PGII) के लिए साझेदारी की शुरूआत की है।
- विदित है कि 27 जून को शुरू की गई इस परियोजना को चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' के ब्लॉक के काउंटर के रूप में उल्लिखित किया जा रहा है।

GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS

सदस्य देश

- संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम

जी 7

जी 7 क्या है?

- 7 देशों का अनौपचारिक समूह।
- यह विश्व की सात सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जो वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- रूस को 1998 में शामिल करते हुए जी 8 का निर्माण, किन्तु 2014 में क्रीमिया के अधिग्रहण के कारण इसे बाहर कर दिया गया।

जी 7 में सन्निहित शक्तियों की प्रासंगिकता

- यह कोई कानून पारित नहीं कर सकता, क्योंकि यह अलग-अलग राष्ट्रों से बना है, जिनकी अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं।
- जी 7 ने 2002 में मलेरिया और एड्स से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वैश्विक प्रतिनिधित्व

सदस्य देश मिलकर वैश्विक जीडीपी का 40% और दुनिया की 10% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जी 7 क्यों महत्वपूर्ण

- जैसा कि ऊपर वर्णित है, जी 7 कोई कानून पारित नहीं कर सकता। यह अलग-अलग राष्ट्रों से बना है, जिनकी अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं।
- यद्यपि, इसके पिछले कुछ निर्णयों का वैश्विक प्रभाव पड़ा है। उदाहरणार्थ- जी 7 ने 2002 में मलेरिया और एड्स से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- यूके में 2021 में होने वाले जी 7 शिखर सम्मेलन से पहले, जी 7 के वित्त मंत्री बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक कर देने पर सहमत हुए।
- इसने विकासशील देशों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की है और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों को संबोधित किया है।

जी 7 में विमर्श के विभिन्न बिन्दु

- जी-7 देशों के बीच रूस पर प्रतिबंध, चीन, ईरान, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और कोरोना समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी है।
- सम्मेलन में चीन, ईरान और रूस को लेकर कड़ा रुख अपनाने के संकेत दिए गए हैं। साथ ही पूर्वी और दक्षिण चीन सागर की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की गई है।
- जी-7 देशों ने पेरिस समझौते को प्रभावी करने के लिए एक क्लाइमेट क्लब बनाने की सहमति व्यक्त की है।
- वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए जी-7 देशों ने इस वर्ष 14 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट (PGII)

पृष्ठभूमि

- बुनियादी ढांचे की योजना की घोषणा पहली बार जून 2021 में यूके में गत वर्ष के जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी।
- ध्यातव्य है कि उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने इसे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W) फ्रेमवर्क नाम से संबोधित किया था।
- यद्यपि, इसने बहुत प्रगति दर्ज नहीं की, क्योंकि योजना की समयावधि या फंडिंग स्रोत के बारे में विवरण स्पष्ट नहीं था।

- इस बार पहल को आधिकारिक तौर पर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट (PGII) के रूप में लॉन्च किया गया है।

उद्देश्य

- इसकी घोषणा निम्न और मध्यम आय वाले देशों की विशाल बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पारदर्शी बुनियादी ढांचा साझेदारी विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी।
- अमेरिका और सहयोगियों के आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों में सहयोग करेगा।

पीजीआईआई के अंतर्गत वित्तपोषण

वित्तपोषण

- अमेरिका ने आगामी 5 वर्षों में 200 अरब डॉलर के सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- यह अनुदान, कर्ज और निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने में सहयोग करेगा।
- इसके अलावा अन्य देश मिलकर कुल 600 अरब डॉलर का सहयोग करेंगे।

कार्य क्षेत्र

जलवायु संकट निदान, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, नई ऊर्जा तकनीकी और क्लीन एनर्जी को विकसित करने पर बल।	5 जी – 6 जी तकनीकी विकास के लिए विश्वसनीय वेंडर का सहयोग लेकर सुरक्षित सूचना नेटवर्क का विकास करना।	हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्टर को विकसित करने और लैंगिंक भेदभाव को समाप्त करने के लिए आवश्यक सहयोग करना।

चीन की बुनियादी ढांचा परियोजना और पीजीआईआई

- अनिवार्य रूप से जी 7 देशों - अमेरिका, कनाडा, इटली, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान और यूरोपीय संघ ने वैश्विक स्तर पर चीन द्वारा शुरू और वित्तपोषित की जा रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के दृष्टिगत इसके लिए अपना वैकल्पिक तंत्र प्रस्तुत करने के उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया है।

- ज्ञातव्य है कि पीजीआईआई और बीआरआई दोनों का घोषित उद्देश्य वैश्विक व्यापार और सहयोग को बढ़ाने के लिए सड़कों, बंदरगाहों, पुलों, संचार व्यवस्थाओं आदि जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए देशों के लिए सुरक्षित वित्तपोषण में सहायता प्रदान करना है।

जलवायु परिवर्तन-लचीली बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित

- जी 7 के अनुसार, यह पहल पारदर्शी होगी, जो जलवायु परिवर्तन-लचीली बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित होने के साथ लैंगिक समानता और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी।
- सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से वित्तपोषण के साथ लगभग एक दर्जन परियोजनाएं पहले ही संचालित हैं।
- अमेरिकी राष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि फंड का आशय "दान या सहायता" नहीं है, अपितु यह ऋण है, जो दोनों देशों (उधार देने और प्राप्त करने वाला) के लिए लाभप्रद होगा।

पीजीआईआई और भारत

- जो बाइडन ने भारत के लिए 3 करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की है।
- इसके अंतर्गत अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम (डीएफसी) ओम्निवोर एग्रीटेक एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी फंड-3 में तीन करोड़ डॉलर का निवेश करेगा।
- विदित है कि इस फंड का उपयोग भारत में कृषि, खाद्य प्रणाली, जलवायु एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े उद्यमों में निवेश के लिए किया जाएगा।
- इस फंड का उपयोग उन कंपनियों में निवेश के लिए किया जाएगा, जो खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करने और भारत में जलवायु लचीलापन और जलवायु अनुकूलन दोनों को बढ़ावा देने में सहयोगी होगा।
- साथ ही साथ छोटे-छोटे खेतों की लाभप्रदता और कृषि उत्पादकता में सुधार करेगा।
- भारत के अलावा, पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका के देशों में परियोजनाओं की घोषणा की गई है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस